बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 168 ● नई दिल्ली ● शनिवार 18 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

कानून मंत्री ने कल सदन में पत्नी के लिए कविता पढ़ी, मुझे घर में बहुत डांट पड़ी- किरेन रीजीजू

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) लोकसभा में शुक्रवार को उस समय हल्के-फुल्के क्षण देखने को मिले जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने मजाकिया लहजे में कहा कि कानून मंत्री ने कल सदन में पत्नी को समर्पित कविता पढ़ी, जिसके बाद मुझे घर में बहुत डांट पड़ी। लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान ऐसे क्षण देखने को मिले। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि कल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने भाषण के अंत में कविता पढ़ी थी तो मैं भी एक कविता पढ़ूंगा।

संसद में राहुल के बयान पर हंगामा- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- देश से माफी मांगें; ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र

नई दिल्ली । लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े तीन संशोधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए।

राहुल के बयान पर सत्ताधारी दल के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में शोर-शराबा और नारेबाजी शुरू हो गई। उन्होंने सरकार से 2023 के महिला आरक्षण विधेयक को दोबारा लाने की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष इसे तुरंत लागू कराने में पूरा सहयोग देगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सत्ता और प्रतिनिधित्व देने से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यही सरकार की वास्तविक मंशा प्रतीत होती है। राहुल गांधी ने कहा, %मैं वापस गार्डन वाली कहानी सुनाता हूं। दादी ने कहा था कि सुनो राहुल मैं चाहती हूं कि तुम अंधेरे में देखना सीखो। अंधेरा में ही असली ताकत है। यह बढ़िया पॉलिटिकल लेशन है। जो असली ताकत होती है वो छिप कर काम करती है अपने आप को दिखाती नहीं है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि सभी जानते हैं एक पार्टनरशिप हमारे जादूगर और बिजनेसमैन के बीच है। इस पर एनडीए सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल ने कहा- मैं पीएम का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने पीएम का नाम नहीं लिया। सर यह पार्टनरशिप मजबूत है, लेकिन छिपी है। जादूगर के पूरे इतिहास में यह ताकत छिपी है।

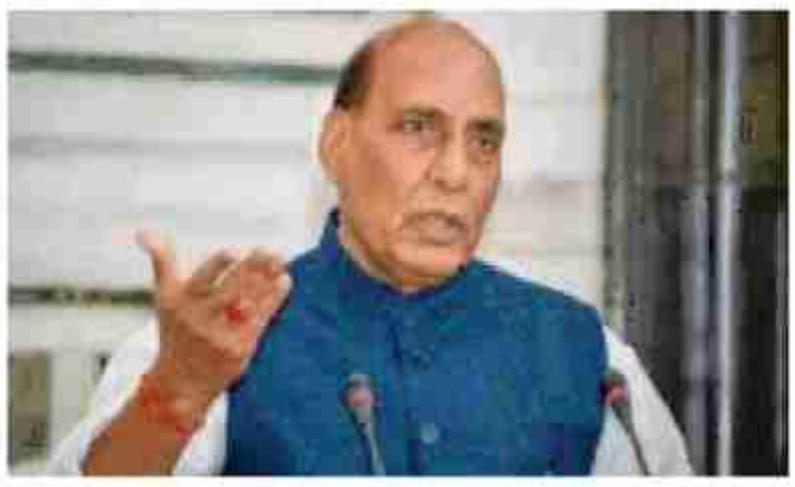

जबसे वे यहां आए तब से यह चल रहा है। भाजपा जानती है कि यह बिल पास नहीं हो सकता। वे इतने बेवकूफ नहीं है वे जानते हैं। इसीलिए उन्होंने चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया। सच यह है कि जादूगर पकड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर, नोटबंदी का जादूगर पकड़ा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रधानमंत्री और देश की गरिमा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना अनुचित है और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे नेता को इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के चुने हुए नेता हैं और उनके प्रति सम्मान बनाए रखना जरूरी है। विवाद बढ़ने पर लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। रिजिजू ने कहा कि उन्हें पूरे भाषण से आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ टिप्पणियां अनुचित हैं और नियमों के खिलाफ हैं। रक्षामंत्री ने कहा है हम भी कह रहे हैं भाषण नियम के तहत दीजिए। बार-बार पीएम का मजाक उड़ाना गलत। पीएम आपका और मेरा नहीं है। इस बीच, राहुल गांधी ने दोबारा बोलने की कोशिश की और कहा कि मौजूदा स्थिति में सत्तारूढ़ दल के भीतर ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, बढ़ते शोर-शराबे के चलते स्पीकर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। सदन में बोलते हुए राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केवल जाति जनगणना शुरू करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसका उपयोग संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व तय करने के लिए किया जाएगा या नहीं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जाति जनगणना को अगले कई वर्षों तक प्रतिनिधित्व से अलग रखने की योजना बना रही है, जो सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है।

दिल्ली को मिली 200 नई ईवी बसों की सौगात- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, 140 देवी बसें भी शामिल

नई दिल्ली । दिल्ली में साफ-सुथरे और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईस्ट विनोद नगर बस डिपो से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही ईस्ट विनोद नगर बस डिपो की नई प्रशासनिक इमारत और मदनपुर खादर बस टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली स्थित ईस्ट विनोद नगर बस डिपो से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में 140 देवी (दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज) बसें भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य खास तौर पर मोहल्लों और अंदरूनी इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी देना है। नई बसों के

शामिल होने के बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर व्यवस्था के तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर करीब 6300 हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने और लोगों को आरामदायक सफर देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ईस्ट विनोद नगर बस डिपो की नई प्रशासनिक बिल्डिंग का उद्घाटन किया। साथ ही दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मदनपुर खादर बस टर्मिनल का भी शुभारंभ किया गया। इन दोनों परियोजनाओं से बस संचालन और यात्रियों की सुविधा में सुधार होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है और हर महीने नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के विकास के लिए बजट की कमी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली के विकास पर विशेष ध्यान है और राजधानी को देश की सबसे तेज विकसित होने वाली शहरों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि नई ईवी बसें दिल्ली के हर इलाके तक बेहतर सेवा पहुंचाएंगी। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली से रोहतक के लिए नई इंटरस्टेट बस सेवा भी शुरू की है, जिससे हरियाणा जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। सरकार आगे भी दूसरे राज्यों के लिए ऐसी सेवाएं बढ़ाने की तैयारी में है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में डीटीसी लगातार मजबूत हो रही है। आने वाले समय में बस बेड़े, रूट नेटवर्क और यात्री सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। नई ईवी बसों के आने से दिल्लीवासियों को साफ, शांत और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा, वहीं शहर में हरित परिवहन को भी नई रफ्तार मिलेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कहा परिसीमन सरकार का नहीं, आयोग का काम

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संसदीय सीटों की संख्या तय करना सरकार का नहीं, बल्कि परिसीमन आयोग का काम है। उन्होंने यह टिप्पणी प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच की। तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उन बयानों पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें उन्होंने दक्षिणी राज्यों के लोकसभा प्रतिनिधित्व पर परिसीमन के संभावित प्रभाव को लेकर चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया था। तिवारी ने कहा कि सरकार केवल सीटों की ऊपरी और निचली सीमा निर्धारित कर सकती है। उन्होंने प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक का हवाला दिया, जिसमें ऊपरी सीमा 850 सीटें तय की गई है। तिवारी के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, यह तय करना परिसीमन आयोग का काम है। तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई से काम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा, मूल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 82 (1ए) में निहित है, जो भारतीय लोकतंत्र का मूलभूत सूत्र है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। उन्होंने आगे समझाया कि इस सूत्र के परिणामस्वरूप, उच्च कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि जनसंख्या नियंत्रण उपायों का सफलतापूर्वक पालन करने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। कांग्रेस सांसद ने सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में परिसीमन प्रक्रिया को हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। तिवारी ने कहा कि सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था, लेकिन इसे 30 महीने बाद अधिसूचित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह क्रम बताता है कि महिला आरक्षण परिसीमन के साथ लागू होगा, जिसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन होगा।

दिल्ली में नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, 29 अप्रैल को होगा इलेक्शन!

नई दिल्ली । दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. 29 अप्रैल को चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है. इसी दिन डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, जिससे सत्ता संतुलन की तस्वीर साफ हो सकती है. इस बार बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है. बीजेपी को मेयर पद जीतने के लिए जरूरी 137 वोटों से अधिक का समर्थन मिलने की संभावना है क्योंकि पार्टी के पास मौजूदा आंकड़ों के अनुसार पर्याप्त संख्या में वोट मौजूद हैं, जिससे उसे सहयोगी दलों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी भले ही बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही हो, लेकिन मौजूदा समीकरण ऐसे हैं कि बीजेपी बिना उनके समर्थन के भी जीत हासिल कर सकती है.

इससे चुनावी मुकाबले में बीजेपी की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है. 31 मार्च को हुई बैठक के बाद स्टैंडिंग कमिटी के 18 में से 9 सदस्य रिटायर हो चुके हैं. इनमें तीन सदस्य हाउस से और छह सदस्य जोन से जुड़े हुए थे. अब इन रिक्त पदों को भरने के लिए भी चुनाव कराया जाएगा, जिससे कमिटी की संरचना में बदलाव आएगा. सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश स्तर से चुनाव कराने की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. नामांकन समाप्त होने के बाद 29 अप्रैल को मेयर का चुनाव कराया जाएगा. उसी दिन डिप्टी मेयर और हाउस से स्टैंडिंग कमिटी के तीन सदस्यों का भी चयन किया जाएगा. एमसीडी के नियमों के अनुसार चौथे और पांचवें साल का कार्यकाल सामान्य श्रेणी का होता है. ऐसे में इस बार महिला, पुरुष या अनुसूचित जाति वर्ग में से किसी भी उम्मीदवार को मेयर बनाया जा सकता है. मेयर चुनाव में केवल निगम पार्षद ही नहीं, बल्कि विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी मतदान करते हैं. मौजूदा स्थिति में बीजेपी के 123 पार्षद और आम आदमी पार्टी के 100 पार्षद हैं. इसके अलावा इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 और कांग्रेस के 9 पार्षद मौजूद हैं. विधायकों की बात करें तो बीजेपी के 11 और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक वोटिंग में हिस्सा लेंगे. साथ ही लोकसभा के सातों सांसद भी मतदान करेंगे. इस तरह कुल मिलाकर बीजेपी के पक्ष में वोटों की संख्या लगभग 141 तक पहुंचती दिखाई दे रही है, जो उसे स्पष्ट बढ़त दिला सकती है.

मैं हटाया गया डिप्टी लीडर हाजिर हूं- राज्यसभा में राघव का तंज; हरिवंश को तीसरी बार उपसभापति बने पर दी बधाई

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में अपनी पार्टी के नेताओं की अनुपस्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए यह बात कही। चड्ढा ने उपसभापति हरिवंश को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई भी दी। सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में सभापति सी. पी राधाकृष्णन से कहा कि उनकी पार्टी के नेता सदन में मौजूद नहीं हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पार्टी के नवनियुक्त उपनेता भी सदन से अनुपस्थित हैं। चड्ढा ने स्वयं को पार्टी के हाल ही में हटाए गए उपनेता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दीं। चड्ढा ने हरिवंश के साथ अपने संबंधों को खट्टा-मीठा बताया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस रिश्ते को मधुर बनाने का प्रयास करने की बात कही। चड्ढा ने सभापति सी. पी राधाकृष्णन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब से स्पीकर ने पदभार संभाला है, सांसदों को शून्यकाल सत्र के दौरान बोलने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

अपनी पार्टी के नेताओं की अनुपस्थिति पर तंज

राघव चड्ढा ने राज्यसभा में अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसके साथ ही, उन्होंने अपनी पार्टी के नए नियुक्त उपनेता की अनुपस्थिति का भी जिक्र किया। चड्ढा ने स्वयं को पार्टी के हाल ही में हटाए गए उपनेता के रूप में

सदन में मौजूद बताया। यह टिप्पणी सदन में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई।

आप ने राघव चड्ढा को हाल ही में उपनेता पद से हटाया था

आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर संसद में पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया था। आप ने कहा था कि उनकी निष्क्रियता पार्टी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, राज्य आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा और पार्टी नेता कुलदीप सिंह धींगरा ने एक संयुक्त बयान में कहा कि चड्ढा की कई महत्वपूर्ण मामलों पर चुप्पी निराशाजनक थी। पंजाब के वित्त मंत्री ने संसद में नहीं उठाए गए कई वित्तीय मामलों पर प्रकाश डाला। इनमें ग्रामीण विकास निधि के लगभग 8,500 करोड़ रुपये के लंबित होने और लगभग 60,000 करोड़ रुपये के जीएसटी-संबंधित नुकसान का मामला शामिल है। चीमा ने जीएसटी मुआवजे में बदलाव से जुड़े वित्तीय झटकों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धन की कमी के मुद्दों का भी उल्लेख किया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने उच्च सदन के उपनेता पद से हटा दिया था। इसके साथ उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। सांसद राघव चड्ढा ने खुद पर लगाए आरोपों पर सफाई दी थी। चड्ढा ने कहा था कि मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। एक जैसी भाषा और एक जैसे आरोप। पहले मुझे लगा कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन फिर लगा कि एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। उन्होंने कहा कि जब भी विपक्ष सदन से वॉकआउट करता है तो मैं भी बाहर निकला हूं। संसद में हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप उसकी फुटेज निकालकर दिखा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाले प्रस्ताव पर आप के किसी नेता ने साइन नहीं किया था। राघव चड्ढा ने घुरंधर फिल्म का संवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि घायल हूं, इसीलिए घातक हूं।

सांस्कृतिक उपेक्षा

आज के दौर में समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों पर लव जिहाद एक निरंतर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रश्न यह उठता है कि इस सोच की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे प्रेम के मार्ग में सब कुछ संभव है–यह धारणा रातों-रात पैदा नहीं हुई। सत्य तो यह है कि यह कोई तात्कालिक घटना नहीं, बल्कि वर्षों से नियोजित एक सुविचारित योजना है, जिसे हम समय रहते समझ नहीं पाए। इस योजना का सूत्रपात फिल्मों के माध्यम से हुआ। यदि हम अतीत पर दृष्टि डालें, तो एक वह समय था जब हिंदी फिल्म जगत में हिंदू कलाकारों का वर्चस्व था। उस काल में सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ भिन्न थीं। किंतु, जैसे ही सिनेमा जगत में एक विशेष समुदाय के कलाकारों–शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और सैफ अली खान–का युग आया, दर्शकों की मानसिकता बदलने लगी। इन कलाकारों को परदे पर अत्यंत चॉकलेटी और रोमांटिक प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके विपरीत, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों की छवि केवल मारधाड़ और एक्शन हीरो तक सीमित कर दी गई। परिणाम स्वरूप, युवा मन में यह धारणा घर कर गई कि वे कलाकार अधिक संवेदनशील और प्रेम करने वाले हैं। फिल्मों के इसी काल्पनिक चित्रण का सहारा लेकर वास्तविक जीवन में भी प्रेम को एक जाल की तरह बिछाया गया, जिसमें युवतियां सरलता से उलझती चली गईं। इस समस्या की जड़ें केवल बाहरी आक्रमण में नहीं, बल्कि हमारे अपने सांस्कृतिक कटाव में भी है। आज से 25-30 वर्ष पूर्व, हिंदू परिवारों में रामायण, महाभारत और शिव-पार्वती जैसे पौराणिक धारावाहिकों को देखने और उन पर चर्चा करने की परंपरा थी। बुजुर्गों के अनुभवों और धर्म चर्चा से बच्चों के मन में अपने मूल्यों के प्रति एक रक्षा कवच बना रहता था। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में आज के हिंदू बच्चे अपने धर्म और संस्कृति के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते। जब उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, तो वे इसे पुराने विचार थोपना मानकर अपनों को ही भला-बुरा कहना शुरू कर देते हैं। धर्म का ज्ञान न होने के कारण, अन्य मतों के लोग उन्हें आसानी से भ्रमित कर लेते हैं। यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोग भी अपनी ही मूल संस्कृति के विरुद्ध दुष्प्रचार करने लगते हैं। आज सार्वजनिक स्थानों जैसे मेट्रो और बाजारों में यह अंतर स्पष्ट दिखता है। जहाँ अन्य समुदायों के बच्चे अपने धार्मिक प्रतीकों और ग्रंथों के प्रति समर्पित रहते हैं, वहीं हमारे युवा अत्यधिक उदारवाद के भ्रम में वास्तविकता से आँखें मूंदे हुए हैं। समाचारों और सोशल मीडिया पर निरंतर चेतावनियाँ दी जा रही हैं, किंतु एक बड़ा वर्ग तब तक सचेत नहीं होता जब तक वह स्वयं संकट में न फँस जाए। पीके जैसी फिल्मों का उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ हिंदू आस्थाओं का उपहास उड़ाया जाता है और पड़ोसी देशों या अन्य समुदायों के प्रेम को महिमामंडित किया जाता है। विडंबना यह है कि आज डिजिटल मंच और सर्च इंजन भी इन संवेदनशील विषयों को काल्पनिक या मनगढ़ंत बताकर प्रस्तुत करते हैं, जो सत्य की खोज करने वालों को और अधिक भ्रमित करता है। वर्तमान में जिस प्रकार की घटनाएँ समाज के सामने आ रही हैं, वे चिंता का विषय है। हाल ही में टीसीएस जैसे बड़े संस्थानों से जुड़े मामलों ने समाज को झकझोर कर रख दिया है, फिर भी यह देखने में आ रहा है कि युवा वर्ग अभी भी पूरी तरह जागरूक नहीं हो रहा है। आज का युवा अक्सर वास्तविकता से दूर एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा है, जहाँ वह ठोस तथ्यों के बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। आज के दौर में सोशल मीडिया और रील्स का प्रभाव युवाओं पर बहुत गहरा है। कई प्रभावशाली व्यक्ति अपनी प्रस्तुति के माध्यम से एक ऐसा नैरेटिव पक्ष खड़ा करते हैं, जो युवाओं को भ्रमित कर सकता है। अक्सर -मेरा वाला अलग है- जैसी मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता है, जो कई बार कड़वी वास्तविकता की अनदेखी करने जैसा होता है। इस तरह के उदाहरण समाज के सामने एक गलत मिसाल पेश करते हैं और युवाओं को तर्कसंगत होने के बजाय भावुक बना देते हैं। समाज में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अन्य समुदायों के युवा अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को लेकर अत्यंत सजग और संगठित रहते हैं। इसके विपरीत, हिंदू युवा वर्ग को भी अब अपनी सांस्कृतिक विरासत और जड़ों के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। केवल आधुनिकता की दौड़ में शामिल होकर अपनी पहचान को भुला देना किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। ठीक है भारत सर्व धर्म समभाव वाला देश है। सबको अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने और पालन करने की पूरी आजादी है। लेकिन यह भी उतना ही कटु सत्य है कि कुछ अवांछित व शरारती तत्वों द्वारा अन्य सर्वमान्य धर्म के विरुद्ध अवांछित टीका टिप्पणी की जाती है। जिस पर नितांत अंकुश आवश्यक है। लव जिहाद केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जब तक संपूर्ण हिंदू समाज वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से संगठित नहीं होगा, तब तक ऐसी योजनाएँ सफल होती रहेंगी। शत्रु हमारी आपसी फूट और अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं। यह समय है कि हम अपनी गौरवशाली विरासत को पहचानें और अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल साक्षर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से शिक्षित भी बनाएँ। युवाओं के लिए विचारणीय बिंदु- स्वयं की सुरक्षा और विवेक- किसी भी रिश्ते या मित्रता में पड़ने से पहले वास्तविकता और तथ्यों की जाँच करना अनिवार्य है। सपनों की दुनिया से बाहर निकलें- सोशल मीडिया की चमक-धमक और रील की दुनिया से बाहर आकर धरातल की सच्चाइयों को समझना बेहद जरूरी है। धर्म और संस्कृति का सम्मान- अपनी संस्कृति और इतिहास को जानना केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपनी पहचान को सुरक्षित रखने का एक माध्यम है। अब समय आ गया है कि युवा वर्ग जागृत हो और केवल व्यक्तिगत हितों या भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि समाज और अपनी संस्कृति के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले।

बिहार के नए सम्राट

अतीत हो या वर्तमान बिहार स्वयं देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है। बिहार सिर्फ भारत का एक राज्यभर नहीं है बल्कि एक संस्कृति है। धार्मिक समागमों और सामंजस्य की धरोहर भी है। बिहार चाणक्य की धरती है। गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य की भूमिका को कौन भूला सकता है। यह भगवान महावीर और बुद्ध की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यह सिखों के दशम गुरु गोविन्द सिंह जी की मातृ भूमि है। यह कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रवादी कविताएं इसी धरा से उपजी है। आर्य भट्ट जैसे विद्वान ने बिहार से ही गणित और खगोलीय अध्ययन में दुनिया को आधारभूत ज्ञान दिया था। वैशाली का प्राचीनतम गणतंत्र बिहार की ही देन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की राजनीति में आए निर्णायक मोड़ का श्रेय बिहार को ही जाता है। जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी धरती से किया था। बुधवार को सम्राट चौधरी के साथ ही राज्य में सम्राट युग का आगाज हो गया है। 9 वर्ष पहले जब वे भाजपा में शामिल हुए थे तब उन्होंने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यद्यपि राजनीति की क, ख, ग उन्होंने अपने पिता शकुनि चौधरी से ही सीखा।

नीतीश शासन समाप्त होने के साथ ही अब बिहार में राजनीतिक दशा और दिशा के पूरी तरह से बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की सियासत ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ी हुई है।

पिछले 20 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता का केन्द्र बने हुए थे और पूरी सियासत उनके इर्द-गिर्द ही सिमटी हुई थी। बीजेपी बैक डोर पर थी लेकिन अब सत्ता की गाड़ी का स्टेयरिंग पूरी तरह से भाजपा के हाथ में आ चुका है। स्पष्ट है कि राज्य में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अब राजनीतिक मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भाजपा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ होगा और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की जनता दल (यू) बैकफुट पर आ जाएगी। नीतीश के दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य बनने से जनता दल (यू) का जनाधार खिसक सकता है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते भाजपा खुलकर हिन्दुत्व का दांव नहीं खेल पाते थे, क्योंकि नीतीश का वोट बैंक कुर्मी-कोइरी और अति पिछड़ा वर्ग रहा। नीतीश ने हमेशा सामाजिक न्याय के एजेंडे का समर्थन किया। राज्य की राजनीति क्या करवट लेती है। यह भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल सम्राट चौधरी के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज उनके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद उनसे लोगों की अपेक्षाएं भी कम नहीं है। लोगों ने 2 दशक तक नीतीश कुमार का राज देखा है। बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल कर नीतीश ने सुशासन कायम किया तो विकास की गंगा भी बही। सड़क, पुल, बिजली और पानी जैसी ढांचागत सुविधाओं से बिहार लैस हुआ है तो इसके पीछे नीतीश कुमार की सुविचारित योजनाएं रही हैं। बाद के दिनों में नीतीश भले कमजोर पड़े, लेकिन पहले टर्म में उन्होंने अपराध नियंत्रण की दिशा में जो काम किए उसे उस दौर की पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी। अब बिहार की बागडोर सम्राट चौधरी के हाथ में है। भाजपा को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य 75 साल बाद मिला है। इस ऐतिहासिक दौर की जिम्मेदारी सम्राट को मिलना सामान्य बात नहीं है।

अब सम्राट के सामने अपनी काबिलियत साबित करने की बारी है। उन्हें 5 ऐसी बड़ी चुनौतियां विरासत में मिली हैं जिन पर कायदे से उन्होंने काम कर लिया तो उनकी गिनती यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने वाले योगी आदित्यनाथ की कतार में होने लगेगी। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए उन्हें नरेंद्र मोदी के अंदाज में काम करना होगा। बिहार में भाजपा को और आगे ले जाने की सियासी चुनौती भी उनके सामने है। उनके सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, औद्योगिक कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव और गरीबी मुंह बाये खड़ी है। बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार है। बिहार में मल्टी डाइमेंशनल गरीबी दर 33.76 प्रतिशत है, जो देश में सबसे ऊंची है। 2015-16 में वह 51.91 फीसदी थी। सुधार तो हुआ लेकिन अभी भी 3.77 करोड़ लोग गरीबी में हैं। बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोग यानि करीब एक-चौथाई युवा बाहर काम करते हैं। दो में से तीन घरों में कम से कम एक सदस्य दूसरे राज्य में है। पिछले वर्षों भी यही ट्रेंड जारी रहा। लालू-राबड़ी और नीतीश के शासन में भी बिहार के लाखों युवा दिल्ली, सूरत, मुम्बई, बेंगलुरु, पंजाब में चले गए क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपए है। यानि राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 32.37 फीसदी है। राज्य की अर्थव्यवस्था 49.6 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। मैन्यूफैक्चरिंग पर निर्भरता सिर्फ 5.7 प्रतिशत है। बिहार में जनसंख्या दर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक विकास धीमा है। फैक्ट्रियां कम हैं और मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर बहुत छोटा है। हर साल बाढ़ राज्य का बहुत नुकसान कर देती है। बिहार में नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को सत्ता संभालने के बाद जो लकीर खींची, वो इतनी बड़ी है जिसका कोई ओर-छोर नहीं है। नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात को मानते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने अपने ऊपर पूरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक दाग तक नहीं लगने दिया। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। क्राइम कंट्रोल से लेकर पुलिस की छवि आम जनता के बीच सही रहे, कार्रवाई निष्पक्ष हो तभी सम्राट चौधरी बतौर सीएम बिहार के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे। ये इतनी बड़ी चुनौती है कि इसमें हुई एक भी गलती भारी पड़ सकती है। ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी के लिए नीतीश की खींची लकीर के बराबर लाइन बनाना भी एक बड़ी चुनौती ही है। नीतीश कुमार पर कभी जाति-पाति के आरोप नहीं लगे। सम्राट चौधरी को भी इन सब चुनौतियों से जूझना होगा।

सम्पादकीय...

नैतिक नेतृत्व के सवाल

वैश्विक राजनीति में उस समय एक असामान्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टकराव सामने आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और वेटिकन के प्रमुख पोप लियो चौदहवें के बीच खुला विवाद छिड़ गया। यह विवाद केवल शब्दों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि युद्ध, नैतिकता और नेतृत्व के दो विपरीत दृष्टिकोणों की टकर बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पोप लियो चौदहवें ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने युद्ध को मानवता के खिलाफ बताते हुए शांति और संवाद का आह्वान किया। उनके इस बयान को एक नैतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, जो विश्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश थी। लेकिन यह रुख सीधे तौर पर ट्रम्प की आक्रामक विदेश नीति के खिलाफ था। डोनाल्ड ट्रम्प ने इस आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पोप पर कई व्यक्तिगत और राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पोप ईरान के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं और -कमजोर- नेतृत्व दिखा रहे हैं। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान ने हाल के महीनों में हजारों निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या की है और ऐसे देश के पास परमाणु हथियार होना -पूरी तरह अस्वीकार्य- है। यह बयान उनके उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति का प्रदर्शन सर्वोपरि है। विवाद तब और गहरा गया जब ट्रम्प ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से निर्मित छवि साझा की, जिसमें वे खुद को एक दिव्य स्वरूप में दिखाते नजर आए। इस छवि में वे एक धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत थे, जिसके चारों ओर सैन्य शक्ति और समर्थकों का चित्रण किया गया था। इस कदम की व्यापक आलोचना हुई और इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान माना गया। बढ़ते विरोध के बाद उन्हें यह पोस्ट हटानी पड़ी, लेकिन तब तक यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका था। इस विवाद में ईरान ने भी खुलकर प्रतिक्रिया दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अन्य नेताओं ने पोप के समर्थन में बयान दिए और ट्रम्प की आलोचना की। उन्होंने इस छवि को धार्मिक अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह टकराव केवल अमेरिका और वेटिकन के बीच नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। इस पूरे प्रकरण ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है- क्या वैश्विक नेतृत्व केवल शक्ति और सैन्य क्षमता पर आधारित होगा, या उसमें नैतिकता और मानवीय दृष्टिकोण की भी जगह होगी ट्रम्प का रुख जहां कठोर और रणनीतिक है, वहीं पोप का दृष्टिकोण शांति, सह-अस्तित्व और संवाद पर आधारित है। आज की दुनिया में, जहां युद्ध और संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह टकराव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सही नेतृत्व की परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्या ताकत ही समाधान है, या फिर संवाद और सहानुभूति ही स्थायी शांति का मार्ग दिखा सकते हैं अंततः, डोनाल्ड ट्रम्प और पोप लियो चौदहवें के बीच यह विवाद केवल दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की टकर है–एक जो शक्ति में विश्वास करती है, और दूसरी जो मानवता में। आने वाले समय में यह टकराव वैश्विक राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित कर सकता है।

नोएडा मज़दूर आंदोलन- अब अपनों की तलाश में भटक रहे परिजन, पुलिस नहीं दे रही कोई जवाब

नोएडा के फेस-2 थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में परिवार अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है, तो कोई अपने पति या भाई को।

कई लोगों का आरोप है कि उनके परिजनों को पुलिस उठाकर ले गई, लेकिन यह तक नहीं बताया जा रहा कि उन्हें कहां रखा गया है। नोएडा में सोमवार 13 अप्रैल को हुए मजदूर आंदोलन के बाद माहौल फिलहाल शांत है लेकिन मजदूर परिवारों की परेशानी अब और बढ़ गई है और हर कोई अपनों को तलाश रहा है। नोएडा के फेस-2 थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में परिवार अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है, तो कोई अपने पति या भाई को। कई लोगों का आरोप है कि उनके परिजनों को पुलिस उठाकर ले गई, लेकिन यह तक नहीं बताया जा रहा कि उन्हें कहां रखा गया है। परिजनों का कहना है कि वे लगातार थानों, अदालतों और जेलों के चक्कर काट रहे हैं–सूरजपुर कोर्ट, डासना जेल, अलग-अलग थाने–लेकिन कहीं से भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि थाने के बाहर खड़े होने तक की अनुमति नहीं दी जा रही और पूछताछ करने पर उन्हें डांटकर भगा दिया जाता है।

मेरा पति कहां है?

नेहा बार-बार थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन उन्हें हर बार धक्के देकर और डांटकर वहां से हटा दिया जा रहा है। नेहा, के पति सोमवार राकेश गायब है। उनके साथ उनकी माँ, जो राकेश की सास है, भी मौजूद थीं। दोनों ही बेहद व्याकुल और भावनात्मक स्थिति में थीं। बातचीत के दौरान नेहा इतना घबराई हुई थीं कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं और बार-बार सिर्फ एक ही सवाल दोहरा रही थीं– मेरा पति कहां है, मुझे बता दीजिए, वो कहाँ है? नेहा का कहना है कि उनके पति राकेश किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं थे। उनके अनुसार, राकेश सुबह काम के सिलसिले में शक्ति (संभवतः किसी औद्योगिक क्षेत्र) गए थे, लेकिन वहाँ काम बंद होने के कारण वे दिल्ली स्थित अपने ससुराल चले गए। बाद में जब वे वहाँ से वापस लौट रहे थे और फेस-2 इलाके में पहुँचे, तभी रास्ते से पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले लिया। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। नेहा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में वह कम से कम 5 से 10 बार थाने जा चुकी है, लेकिन हर बार उन्हें बिना कोई स्पष्ट जानकारी दिए भगा दिया गया। उनका कहना है कि पुलिस न तो यह बता रही है कि उनके पति को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, और न ही यह कि उन्हें कहाँ रखा गया है। नेहा के दो छोटे बच्चे हैं, जिन्हें वह घर पर छोड़कर अपने पति की तलाश में भटक रही हैं। उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक है और वे लगातार यही मांग कर रही हैं कि अगर उनके पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो कम से कम इसकी आधिकारिक जानकारी दी जाए। अन्यथा, यदि वे लापता हैं, तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाए। यह मामला भी उन कई घटनाओं में से एक है, जिनमें परिजन अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में परिवारों की चिंता और असुरक्षा लगातार बढ़ती जा रही

बेटे की तलाश में भटकता पिता

एक और मामला अनिल कुमार का है, जो अपने 18 वर्षीय बेटे अंकुश की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। अनिल कह रहे हैं कि उनके बेटे अंकुश हाल ही में गांव से नोएडा आया था और किसी भी तरह की मजदूरी या प्रदर्शन से उसका कोई संबंध नहीं था। अनिल कुमार का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली कि कुछ लोगों को एक फैक्ट्री के पास से उठाया गया था, जिसमें उनका बेटा भी हो सकता है। तब से वे सूरजपुर कोर्ट, डासना जेल और थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है।

अभिलाषा अपने एक रिश्तेदार के साथ थाना परिसर के बाहर खड़ी थीं और अपने भाई के बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस बार-बार उन्हें वहाँ से हटने के लिए कह रही थी और डांटकर भगा रही थी। पुलिस का तर्क था कि थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा न हो और इस तरह की चर्चाएँ फैलने से रोकी जा सकें, ताकि स्थिति और न बिगड़े या मीडिया तक बात न पहुँचे। अभिलाषा के भाई अमित, जिन्हें आसिफ के नाम से भी जाना जाता है, पिता बच्चेलाल के पुत्र हैं और उनकी उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार, वे मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे से ही थाने में हैं, लेकिन तब से अब तक उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। अभिलाषा ने बताया कि उनकी अपने भाई से आखिरी बार सोमवार सुबह करीब 10 बजे बातचीत हुई थी। उस दौरान उन्होंने बताया था कि इलाके में तनाव बढ़ रहा है और झगड़े की स्थिति बन रही है, जिससे वे काफी परेशान और घबराए हुए थे। इसके बाद से ही उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिवार का आरोप है कि इसके बाद से उनका फोन बंद जा रहा है और पुलिस की ओर से भी कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है कि उन्हें कहाँ रखा गया है या उनकी क्या स्थिति है। अभिलाषा लगातार अपने भाई की तलाश में इधर-उधर भटक रही है और सिर्फ यह जानना चाहती है कि उनका भाई किस हाल में है।

विजय का परिवार और डासना जेल का सफर

विजय कुमार के छोटे भाई नवीन को पुलिस अपने साथ ले गई थी। परिवार ने पूरी रात अलग-अलग जगहों पर तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में किसी के जरिए पता चला कि उन्हें डासना जेल में रखा गया है। विजय कुमार के अनुसार, उनके छोटे भाई नवीन कुमार, जिनकी उम्र लगभग 21-22 वर्ष है, उनके साथ ही एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करते थे। विजय खुद उनसे थोड़े बड़े हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम पुलिस उनके भाई को अपने साथ लेकर गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। इसके बाद से परिवार लगातार परेशान रहा और रात भर विभिन्न थानों और स्थानों पर जाकर जानकारी जुटाने की कोशिश करता रहा। विजय कुमार ने बताया कि उन्होंने फेस-2 थाना, सूरजपुर कोर्ट समेत कई जगहों पर जाकर पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। अंततः मंगलवार को किसी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें पता चला कि उनके भाई को डासना जेल में रखा गया है। इसके बाद वे अपने परिजनों के साथ डासना पहुँचे, लेकिन अब तक उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। फोन पर बातचीत में विजय कुमार ने कहा कि पूरा परिवार बेहद परेशान है और किसी भी अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को यह जानकारी मिली है कि उनके भाई को डिटेन किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी जांच की जाएगी और यदि कोई निर्दोष पाया जाता है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, परिवार की चिंता अभी भी बनी हुई है। विजय कुमार को आशंका है कि उनके भाई के साथ हिरासत के दौरान मारपीट की गई हो सकती है, क्योंकि अब तक उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि वे फिर से अपने भाई से मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके हालात के बारे में पता चल सके।

पुलिस कार्रवाई पर उठते सवाल

पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है–क्या कार्रवाई के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है? कानून के मुताबिक, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना और उसके परिजनों को सूचित करना जरूरी होता है। लेकिन कई परिवारों का दावा है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ ही, कुछ वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी सामने आए हैं, जिनमें कथित तौर पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं–यहां तक कि महिलाओं के साथ भी। आपको बता दें कि नोएडा के औद्योगिक इलाकों में न्यूनतम वेतन बढ़ाने और काम की शर्तों में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ मजदूरों का आंदोलन सोमवार को कई जगहों पर हिंसा में बदल गया था। कुछ फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस का कहना है कि अब तक 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस मामले में 7 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाने के लिए की जा रही है। साथ ही, पुलिस ने यह भी संकेत दिए हैं कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और बाहरी तत्वों या किसी साजिश की भी पड़ताल की जा रही।

विपक्ष क़ो महिला आरक्षण क़ा विरोध नहीं परिसीमन के साथ जोड़ने का विरोध

वैश्विक स्तरपर भारत की संसदीय राजनीति एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है,जहाँ एक ओर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक प्रयास दिखाई देता है,वहीं दूसरी ओर परिसीमन (डेलिमिटेशन) के माध्यम से राजनीतिक शक्ति संतुलन में संभावित बदलाव ने व्यापक विवाद को जन्म दिया है। संसद के विशेष सत्र में पेश किए गए तीन प्रमुख विधेयक (1) महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन बिल 2026 (2) परिसीमन (डेलिमिटेशन) बिल2026 (3) केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में संशोधन बिल 2026 जहां कानून मंत्री ने संवैधानिक संशोधन और परिसीमन बिल पेश किए, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ासटीक संशोधन विधेयक पेश किया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन,परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े संशोधन ने न केवल राजनीतिक बहस को तेज किया है,बल्कि देश के संघीय ढांचे, प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यह मुद्दा अब केवल महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर बनाम दक्षिण,जनसंख्या बनाम प्रतिनिधित्व और सत्ता बनाम संतुलन की बहस में बदल चुका है। 16 अप्रैल 2026 को विशेष संसद सत्र के पहले दिन सरकार द्वारा पेश किए गए तीनविधेयकों में सबसे अधिक ध्यान महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर केंद्रित रहा। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है,जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही लगभग 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है। तीनों बिलों को संसद में पेश करने के लिए ध्वनि मत से रखने के लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ इसलिए वोटिंग करानी पड़ी वोटिंग के दौरान सरकार को 251 सांसदों का समर्थन मिला,जबकि 185 सांसदों ने विरोध किया। यह स्पष्ट संकेत है कि संसद में यह मुद्दा केवल नीतिगत नहीं बल्कि गहराई से राजनीतिक और क्षेत्रीय विभाजन का विषय बन चुका है। ध्वनि मत के बजाय डिवीजन की मांग ने इस विवाद को और अधिक औपचारिक और गंभीर बना दिया। साथियों बात अगर हम महिला आरक्षण बनाम परिसीमन असली विवाद कहाँ है इसको समझने की करें तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा,बल्कि उसका मुख्य विरोध इस बात से है कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ा गया है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए,न कि इसे जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर टाल दिया जाए दरअसल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए यह आवश्यक शर्त रखी गई थी कि पहले नई जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन के जरिए नई सीटों का निर्धारण किया जाएगा। यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है। विपक्ष इसे एक डिले टैक्टिक यानी देरी करने की रणनीति मानता है,जबकि सरकार इसे संरचनात्मक सुधार का महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हिस्सा बताती है। साथियों बात अगर हम विशेष रूप से परिसीमन का गणित- जनसंख्या आधारितप्रतिनिधित्व का सवाल इसको समझने की करें तो, परिसीमन का मूल उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना होता है। लेकिन भारत में 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण लंबे समय तक स्थिर रखा गया, ताकि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले राज्यों को नुकसान न हो। 1976 में यह तय किया गया कि 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। अब जब 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है,तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्याजनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा यदि ऐसा होता है,तो उत्तर भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश,बिहार,मध्य प्रदेश को अधिक सीटें मिलेंगी,जबकि दक्षिण भारत के अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों जैसे तमिलनाडु,केरल, कर्नाटक की सीटें घट सकती हैं।यही वह बिंदु है जहाँ यह मुद्दा एक राष्ट्रीय बहस से क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर प्रदर्शन किया है,और अब उन्हें सजा के रूप में कमप्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।दक्षिण के राजनीतिक दलों, विशेषकर डीएमके और कांग्रेस, ने इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया है। उनका मानना है कि इससे संसद में दक्षिण की आवाज कमजोर हो जाएगी और राष्ट्रीय नीतियों में उनका प्रभाव घट जाएगा। यह स्थिति भारत के संघीय संतुलन को अस्थिर कर सकती है। साथियों बात अगर हम सत्ताधारी पार्टी का दृष्टिकोण- समान वृद्धि और संतुलन का दावा इसको समझने की करें तो,सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या समान अनुपात में बढ़ाई जाएगी,जिससे किसी राज्य कावर्तमान प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा।पीएम ने संसद में अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह कदम महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए उठाया गया है।सरकार का यह भी दावा है कि परिसीमन आयोग निष्पक्ष रूप से काम करेगा और किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा।उनके अनुसार, यह केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि व्यापक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। साथियों बात अगर हम राजनीतिक आशंका- क्या यह पॉलिटिकल कूप है इसको समझने की करें तो विपक्ष का आरोप है कि यह पूरा कदम एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है,जिससे उन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएँगी जहाँ सत्ताधारी दल का प्रभाव अधिक है। हिंदी भाषी उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी की मजबूत पकड़ को देखते हुए विपक्ष को आशंका है कि परिसीमन के बाद संसद में सत्ता संतुलन और अधिक एकतरफा हो सकता है।यह आशंका केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संरचनात्मक भी है, क्योंकि संसद में सीटों का वितरण सीधे तौर पर नीति निर्माण और संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। साथियों बात अगर हम जनगणना का सवाल- बिना डेटा के निर्णय इसको समझने की करें तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि परिसीमन से पहले जनगणना होनी चाहिए या नहीं। विपक्ष का कहना है कि बिना नई जनगणना के परिसीमन करना तर्कसंगत नहीं है,क्योंकि इससे वास्तविक जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा।सरकार ने संविधान में जनसंख्या की परिभाषा को संशोधित कर यह प्रावधान किया है कि संसद जिस जनगणना को मान्यता देगी,उसी के आधार पर परिसीमन होगा। इससे सरकार को कुछ हद तक लचीलापन मिल जाता है, लेकिन इससे पारदर्शिता पर सवाल भी उठते हैं। साथियों बात कर हम लोकसभा का विस्तार- प्रतिनिधित्व या जटिलता इसको समझने की करें तो लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना एक बड़ा कदम है। यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था को और भी विशाल बना देगा।

इससे प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा,लेकिन साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो सकती है।इतिहास पर नजर डालें तो लोकसभा की सीटें समय-समय पर बढ़ाई गई हैं, लेकिन इस बार का विस्तार अभूतपूर्व है। यह बदलाव न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बता दें लोकसभा में कब-कब बढ़ी सांसदों की संख्या, वर्ष / सीटें 1950/489, 1956/ 494, 1962/ 520, 1973 / 545 (जिसमें 2 एंग्लो इंडियन नामित) 2020+543 (एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त होने से) 2026 /850 (प्रस्तावित) अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि लोकतंत्र का विस्तार या नई असमानता की शुरुआतमहिला आरक्षण और परिसीमन का यह पूरा मुद्दा भारतीय लोकतंत्र के लिए, एक दोधारी तलवार की तरह है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पेंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

अम्बेडकर जयंती पर मंगोलपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा

नई दिल्ली।(इंद्रजीत सिंह) मंगोल पुरी, रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 135 वीं जयंती के शुभ अवसर पर भारत वर्ष के सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजा जाटव द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम शोभा यात्रा की जानकारी प्रेरणादायक है। इस तरह के आयोजन न केवल बाबा साहेब के विचारों को जन-जन तक पहुँचाते हैं, बल्कि समाज में एकता और जागरूकता का संचार भी करते हैं।

कार्यक्रम का भव्य स्वरूप

अपार जनसमूह बाबा साहेब के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। झ्झ पर भीम गीतों और क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से बाबा साहेब के संघर्षों को याद किया गया।

राजा जाटव और गणमान्य अतिथियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।समाज सेवक राजा जाटव ने इस अवसर पर उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए मुख्य बातें साझा की।

शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बाबा साहेब के इस मूल मंत्र को जीवन में उतारने पर जोर दिया।

समानता का अधिकार- भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

युवा शक्ति युवाओं से अपील की गई कि वे शिक्षा के माध्यम से समाज और देश के विकास में अपना योगदान दें।

राजा जाटव के नेतृत्व में सजावट और व्यवस्थाएं अत्यंत सुंदर और व्यवस्थित रहीं।जाति और भेद-भाव से ऊपर उठकर

राजा जाटव ने इस शोभा यात्रा में हर धर्म हर समाज के लोगों को जोड़कर मानवता की मिशाल पेश की इस आयोजन ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाने का कार्य किया।

बाबा साहेब का विजन और समाज सेवा, राजा जाटव जैसे समाज सेवकों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास बाबा साहेब के सपनों के भारत को साकार करने में मदद करते हैं

यह वाकई एक सकारात्मक और एकता का संदेश देने वाली खबर है। दिल्ली के मंगोलपुरी में राजा जाटव के नेतृत्व में निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा की सबसे खास बात इसकी समावेशी प्रकृति रही।

इस यात्रा में एकता और भाईचारे की मिशाल देखने को मिली इस भीम यात्रा में केवल एक समुदाय नहीं,केवल एक धर्म नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख,ईसाई, बौद्ध धर्म सहित हर धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न समाजों और जातियों के लोगों का एक साथ आना क्षेत्र में सामाजिक एकता को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

स्थानीय निवासियों ने कहा कि पहली बार मंगोल पुरी में किसी युवा पीढ़ी ने सामाजिक समरसता पर दिल से काम किया है मंगोल पुरी का हर व्यक्ति राजा जाटव को दिल से दुआ देता है कि आप इसी प्रकार समाज में कार्य करते रहे मंगोलपुरी के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी शोभा यात्रा में इतनी व्यापक और विविध भागीदारी देखी गई।

नकारात्मकता का अंत ऐसी यात्राएं समाज में मौजूद आपसी भेदभाव और कड़वाहट को कम करने में मदद करती हैं।

युवाओं को प्रेरणा नई पीढ़ी के लिए यह आयोजन एक मिसाल है कि धर्म और समाज को बांटने के बजाय जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है।

वहीं सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजा जाटव ने कहा कि मैं मंगोलपुरी के हर व्यक्ति का आभारी हूं जो आपने अपना समय का योगदान देकर शोभा यात्रा को इतना विशाल व भव्य बना दिया। वहीं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिल से जमीनी स्तर पर काम करने वाले महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अपने सभी सम्मानित साथियों का भी आभारी हूं जिनके नाम

वाल्मीकि समाज के प्रधान- संदीप पार्चा, समाज सेवक- राम कुमार भगत जी, नंद राम बागड़ी,राहुल रूखड़, नीता रूखड़, सोनू मकवाना,अजय गुजराती, सुमित सरासर, सुरेंद्र झिंगाला, रेखा दुग्गल, जसवंत बोहत, बिजेंद्र डेडवाल, जय प्रकाश जी,राहुल पहलवान,सतीश जाटव, संजय सर,राम बच्चन,राकेश कुमार निगम, प्रेम सिंह उर्फ लाला, गणेश सांवरियाँ, नरेंद्र सांवरिया, जीतू सांवरिया, नरेश सांवरिया,अमर सांवरिया,वसीम अब्बास अली खान,राजू फरीद, अनामुलक हक आजाद,यूनिस कुरैशी, अमित चौहान,अवधेश भारती,पुष्पा जाटव, मनीषा अदलान, देवेंद्र कुमार देबू,चंद्रपाल, बृजमोहन,राकेश कुमार, डॉ वी.पी सिंह,नासिर खान, मो.सैफ,अमित सैनी, अमित जाटव,लोकेश चौधरी, निरंजन जाटव,जय प्रकाश,शाहिद चौधरी,उमेश जाटव, नीतू उर्फ सुनीता बहन जी, इब्राहिम खान, संजय प्रॉपर्टीज,राहुल उर्फ गोलू,नरेंद्र सांवरिया, जीतू सांवरिया,राज नावरियां, लोकेश चौधरी,श्री मति शीला जी,अनीता वर्मा,भारती सोनी,राकेश कुमार, ललिता जी, अलीशेर,सनोज रिड़लान, विजय जाटव, राजेश कुमार, नागेन्द्र प्रसाद, नरेंद्र भारद्वाज, डॉ अमित गोदारा,जीतू जाटव,तेज सिंह जी,पवन राणा, बृजभान, धर्मेंद्र जाटव,राकेश जी,इत्यादि

स्थानीय निकाय चुनावों पर कड़ी निगरानी, राज्य चुनाव आयोग ने जनरल, पुलिस व व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

चंडीगढ़ ।

हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने आगामी 10 मई को निर्धारित स्थानीय निकाय चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए जनरल, पुलिस एवं व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। आयोग द्वारा वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस एवं एचसीएस अधिकारियों को डिम्ड डिपुटेशन पर नियुक्त करते हुए उन्हें अंबाला, पंचकूला, सोनीपत सहित अन्य संबंधित जिलों में चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की निगरानी हेतु तैनात किया गया है। इन पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रबंधन के सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में दायित्व सौंपे गए हैं। जनरल पर्यवेक्षक, जो वरिष्ठ आईएएस/एचसीएस अधिकारी हैं, आयोग के प्रतिनिधि के रूप में जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए ईवीएम एवं मतदान कर्मियों के रैंडमाइजेशन, नामांकन प्रक्रिया तथा नामांकन पत्रों की जांच, मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों की सीधे आयोग को रिपोर्ट करेंगे।

पुलिस पर्यवेक्षक, जो वरिष्ठ आईपीएस/ एचपीएस अधिकारी हैं, कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करते हुए मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता का आकलन, पुलिस बल एवं होमगार्ड की तैनाती की समीक्षा, शराब निषेध एवं हथियार प्रतिबंध के आदेशों का कड़ाई से पालन तथा रैली एवं लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की निगरानी सुनिश्चित करेंगे। वहीं, व्यय पर्यवेक्षक, जो डीईटीसी अधिकारी हैं, चुनाव में धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए प्रत्याशियों के दैनिक व्यय रजिस्टर की निगरानी, स्थैतिक निगरानी टीम एवं फ्लाइंग स्क्वॉड के साथ समन्वय कर अवैध नकदी या उपहारों के आवागमन पर रोक तथा निर्धारित व्यय सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। ये सभी पर्यवेक्षक 13 मई 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने-अपने आवंटित जिलों में तैनात रहेंगे।

हरियाणा में व्यापारियों को मिलेगा सहायता योजना का लाभ, पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई की गई

चंडीगढ़ । (संवाददाता) हरियाणा सरकार ने व्यापारियों एवं उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं की सुखद पहल की है। इसी के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए सहायता योजनाएं आरंभ की है। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को स्वरूप दिया है जिसके अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत व्यापारी को जानमाल के नुकसान एवं दुर्घटना होने पर, जीवन की क्षति और स्थायी निःशक्त होने पर सरकार द्वारा 5 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत किसी व्यापारी के माल का नुक्सान (आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक की हानि) होने पर राज्य के पंजीकरण व्यापारियों के नुक्सान की भरपाई के लिए करदाता के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार रु 5 लाख से रु 20 तक की सहायता हरियाणा सरकार सुरक्षा न्यास द्वारा प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं के लिए व्यापारी पोर्टल पर 31 मई तक आवेदन कर सकते है।

डॉ, अंबेडकर जन्मोत्सव पर निकाली भव्या शोभा और धम्म यात्रा

नई दिल्ली। (ए.के. चौधरी) दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान, अजमेरी गेट से बाबासाहेब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली (रजि.) के तत्वाधान में बाबा साहब के 135 वे जन्म दिवस के उपलक्ष में एक विशाल धम्मसभा एवं भव्य विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया । शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में बाबा साहब डॉ अंबेडकर जी के जीवन संघर्षों पर आधारित मनमोहक झांकियां, जिसके साथ बैंड बाजे, नफीरी वाले, ढोल ताशे और नगाड़े पर भंगड़ा करते हुए बाबा साहब के अनुयाई शामिल हुए । शोभायात्रा रामलीला मैदान से आरंभ होकर अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्केट, बारा टूटी, पहाड़ी धीरज, मानक पुरा, शीदी पुरा, देशबंधु गुप्ता रोड, देव नगर, आर्य समाज रोड, रैगर पुरा होते हुए अंत में डा. अम्बेडकर भवन पहाड़गंज पर पहुंची । शोभा यात्रा के मार्ग में जगह पर फूलों की वर्षा करके बाबा साहब के अनुयाइयों द्वारा स्वागत किया गया, साथ ही बाबा साहब के अनुयाइयों ने बड़ी संख्या में स्वागत मंचों जिसमें जल पान व छबील की व्यवस्था कर रखी थी। शोभायात्रा में हजारों नर नारियों और युवाओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा का उदघोष करते रहे । मंच पर गायक विनोद जी (अशोक नगर) मंडली द्वारा बाबा साहब जी से संबंधित सुंदर गीतों ने बाबा साहब के अनुयाइयों का मन मोह लिया।

समारोह में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री मान्य राजकुमार आनंद जी, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय संजीव कुमार जी, विधायक मान्य प्रवेश रत्न जी, विधायक मान्य आले मोहम्मद इकबाल जी, पूर्व विधायका मान्या बीणा आनंद जी, निगम पार्षद मान्या उर्मिला महेंद्र गौतम जी, मान्य सी एस भंडारी जी अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, मान्य गोपाल कृष्ण जी अध्यक्ष श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर ट्रस्ट, मान्य सी एस भंडारी जी अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली, मान्य आनंद लाल जी वरिष्ठ समाज सेवक, मान्य महेंद्र गौतम जी वरिष्ठ समाज सेवक मान्य चकित रवि जी चेयरमैन ऑल कैन स्माइल फाउंडेशन, मान्य नीटू शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवक, मान्या निधि खींची जी समाज सेविका (पूर्व मेयर मान्य महेश खींची जी की अर्धांगिनी) आदि -आदि ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने-अपने विचार रखे । मान्य राजकुमार आनंद जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष को बिस्तार से रखा और कहा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारी स्थिति बहुत दयनिय होती ।

संजीव कुमार जी ने भी बाबा साहब के जीवन संघर्ष के साथ समाज को शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देने की बात रखी । भंडारी जी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि देश में अब अम्बेडकर बाद की जरूरत है हमें बुद्ध धम्म के रास्ते पर चलना होगा । वहीं आंनद लाल जी ने भी बाबा साहब जी के जीवन संघर्ष को याद करते हुए कहा की यह समय हमें संगठित होने का है साथ ही बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का है पर जब भी समाज को मेरी आवश्यकता होगी मैं चौबिसों घंटे समाज के प्रति समर्पित रहूंगा।

कमेटी के महामंत्री मान्य उत्तम सिंह ने मंच का सफल संचालन करते हुए बाबा साहब के प्रति अपने विचार रखने से पहले पुष्पांजलि अर्पित की । अभिरक्षक मान्य जय सिंह भारती जी व अध्यक्ष मान्य हंसराज हंस जी ने भी बाबा साहब को पुष्पांजलि देते हुए अपने विचार रखे ।

समारोह में कमेटी के निम्न पदाधिकारीयों व सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ।

जय सिंह भारती (अभिरक्षक), हंसराज हंस (अध्यक्ष), उत्तम सिंह (महासचिव), भगवान दास नागर (कोषाध्यक्ष),सदस्य गण :- प्रकाश चौधरी, मोहनलाल मिमरोट, अनिल कदम, मुकेश कुमार गौतम, घनश्याम, दिनेश कुमार, एच के मानक, सूरजभान कर्दम, जयकिशन भारती, अरविंद कुमार गौतम, प्रदीप कुमार ।

स्वेच्छा से विशेष सहयोगियों में एडवोकेट अरविंद कुमार, होपेंद्र प्रकाश विकल।

दिल्ली समेत आस-पास के शहरों में धूल भरी आंधी के बाद बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) शुक्रवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम बदला रहा है। दोपहर करीब 3 बजे के बाद अचानक तेज हवा चली और देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही आज के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई थी। दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर के समय जहां आसमान में सूर्य देव चमक रहे थे वहीं बाद में घने बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस दौरान चली तेज आंधी ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे मौसम में हल्की ठंडक महसूस की गई। आंधी के कारण सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अचानक बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली लेकिन तेज आंधी ने जनजीवन को कुछ समय के लिए प्रभावित किया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम में इसी तरह बदलाव की संभावना बनी रह सकती है।

लोकसभा में राहुल ने कहा- मेरे और प्रधानमंत्री के पास पत्नी वाला मसाला नहीं है

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पुरुषों के जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उनके और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन में पत्नी वाला मसाला ही नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, महिलाएं एक केंद्रीय शक्ति होती हैं, जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की कल्पना और हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक प्रेरक शक्ति हैं। हम सभी अपने जीवन में महिलाओं, माताओं, बहनों और पत्नियों से बहुत प्रभावित हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसी दौरान उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू की एक टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा, रीजीजू जी ने कहा है, लेकिन न तो मेरे पास और न ही प्रधानमंत्री के पास पत्नी वाला मसला है, इसलिए हमें उस नजरिए से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। लेकिन हमारी मां और बहन हैं। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष के भाषण से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने एक अलग संदर्भ में मजाकिया लहजे में कहा था कि कानून मंत्री (अर्जुन राम मेघवाल) ने कल सदन में पत्नी को समर्पित कविता पढ़ी, जिसके बाद मुझे घर में बहुत डांट पड़ी। राहुल गांधी ने अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा के बृहस्पतिवार के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी बहन ने गृह मंत्री अमित शाह को मुस्कराने के लिए विवश कर दिया, जबकि वह खुद 20 साल में ऐसा नहीं कर पाए।

द्वारका में आधी रात को मुठभेड़- विक्की टक्कर गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित दो आदतन अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी जतिन शर्मा (27) और पवन भंडारी (26) विक्की टक्कर गिरोह से कथित रूप से जुड़े हुए हैं और आठ अप्रैल को डाबरी इलाके में एक व्यक्ति को चाकू से वार कर गंभीर रूप से जख्मी करने की वारदात में शामिल थे। द्वारका के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह (डीसीपी) ने कहा कि पीड़ित के बयान के बाद मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान शर्मा और भंडारी की मुख्य आरोपी के रूप में पहचान हुई। पीड़ित ने बाद में पुलिस को बताया कि दोनों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसे इलाके में दुकान चलानी है तो उसे आरोपियों को पैसे देने होंगे। पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम ने बृहस्पतिवार देर रात धूलसिरास चौक के पास जाल बिछाया और आरोपियों को देर रात 2.10 बजे उस समय रोक लिया जब वे नजफगढ़ की तरफ से स्कूटर पर आ रहे थे। अधिकारी ने बताया, जब शर्मा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, तो उसने पुलिस टीम पर कथित तौर पर गोली चलाई और एक गोली कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी जिससे वह बाल-बाल बच गया। उन्होंने बताया कि इसके जवाब में कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में दो गोलियां चलाईं और एक गोली शर्मा के पैर में लगी। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा, कारतूस और कारतूस के खाली खोखे और एक चोरी का स्कूटर बरामद किया।

'परिसीमन एक राजनीतिक नोटबंदी साबित होगा'- शशि थरूर का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) लोकसभा में शुक्रवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया की तुलना नोटबंदी से करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के लिए खतरा बताया। शशि थरूर ने कहा कि दशकों से महिला आरक्षण का वादा किया गया और इसे टाला गया। आज जब इस पर राजनीतिक सहमति बनी है, तब सरकार ने इसे परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया से बांधकर महिलाओं की आकांक्षाओं को बंधक बना लिया है। थरूर ने सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा, आपने परिसीमन का प्रस्ताव वैसी ही जल्दबाजी में पेश किया है जैसी नोटबंदी के समय दिखाई थी। हम सब जानते है कि नोटबंदी ने देश का क्या हाल किया था। परिसीमन भी एक राजनीतिक नोटबंदी साबित होगा, इसे मत कीजिए। थरूर ने उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई। उन्होंने तर्क दिया कि केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण और मानव विकास में बेहतरीन काम किया है। यदि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ, तो जनसंख्या नियंत्रण में विफल रहने वाले राज्यों को अधिक राजनीतिक ताकत मिलेगी और अच्छा काम करने वाले राज्य हाशिए पर चले जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आर्थिक रूप से समृद्ध और विकासशील राज्यों की आवाज को दबाया गया, तो इससे देश के संघीय ढांचे पर बुरा असर पड़ेगा। उनके अनुसार, यह बहुसंख्यकवाद को तानाशाहीपैदा करने जैसा होगा।

नगर निगम चुनाव में आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें अधिकारी- आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण

चंडीगढ़ । हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने नगर परिषदों, नगर समितियों एवं नगर निगमों के आगामी चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शुक्रवार को यहां रेस्ट हाउस में सोनीपत और रेवाड़ी के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनाव तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की और स्पष्ट किया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पर्व है और इसकी पवित्रता बनाए रखना प्रशासन, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा आमजन की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी सुनिश्चित करें। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने पर विशेष बल दिया। आयुक्त ने मतदान को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में आयोजित करने पर जोर देते हुए कहा कि मतदाताओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा हेल्प डेस्क स्थापित कर मतदाताओं को बूथ संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अंतरराज्यीय सीमाओं, विशेषकर उत्तर प्रदेश से लगते क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। पुलिस नाकों पर 24 घंटे सतर्कता बरती जाए ताकि अवैध शराब, नकदी, उपहार सामग्री या अन्य प्रलोभनों के उपयोग को रोका जा सके। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हुए आयुक्त ने कहा कि जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगना पूर्णतः प्रतिबंधित है। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैलियों और सभाओं के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी तथा नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विरोधियों की आलोचना केवल नीतियों और कार्यों तक सीमित रहे; व्यक्तिगत आरोप या भ्रामक प्रचार से बचना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देना, डराना-धमकाना या किसी प्रकार का प्रलोभन देना दंडनीय अपराध है। मतदान से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा तथा मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पूरी तरह निषिद्ध होगा। निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि मतदान दिवस से पूर्व निर्धारित अवधि में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार अपने समर्थकों को भी इसके प्रति जागरूक करें। निजी संपत्ति के उपयोग को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी की संपत्ति पर पोस्टर, बैनर या नारे लिखना प्रतिबंधित है।

दिल्ली में यमुना के उफान से निपटने की तैयारी, राजधानी में बनेगी 4.72 किमी लंबी सुरक्षा दीवार

नई दिल्ली । दिल्ली में हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले इलाकों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यमुना के बढ़ते जलस्तर से बचाव के लिए राजधानी में एक लंबी सुरक्षा दीवार बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसे 2027 के मॉनसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि मजनूं का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक करीब 4.72 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी. यह परियोजना बजट का हिस्सा है और इसे बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यह दीवार यमुना के पानी को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकेगी. खासतौर पर सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और मजनूं का टीला जैसे इलाकों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है, जहां हर साल बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है. दिल्ली में बाढ़ का खतरा हर साल बढ़ता जा रहा है. 2023 में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है. वहीं, 2025 में भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहते हुए 207.48 मीटर तक पहुंच गई थी, जिससे कई इलाके पानी में डूब गए थे. इस परियोजना की नींव अगस्त 2024 में तैयार संयुक्त बाढ़ समिति की रिपोर्ट पर रखी गई थी. विशेषज्ञों द्वारा किए गए हाइड्रोलिक मॉडलिंग और डेटा विश्लेषण के बाद इस दीवार को दीर्घकालिक समाधान के रूप में सुझाया गया था.

मुख्यमंत्री रेखा का कहना है कि मौजूदा तटबंध भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. नई दीवार न सिर्फ बाढ़ के पानी को रोकने में मदद करेगी, बल्कि नदी किनारे कटाव को भी कम करेगी और गंदगी फेंकने पर रोक लगाने में सहायक होगी. हालांकि, इस योजना से सभी विशेषज्ञ सहमत नहीं हैं. पर्यावरण से जुड़े जानकारों का मानना है कि ऐसी संरचनाएं नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं और बाढ़ के खतरे को दूसरे इलाकों में बढ़ा सकती हैं. वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ वेंकटेश खन्ना ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि यमुना के किनारे पहले से ही फ्लड प्लेन्स बने हुए हैं, जो नेचर ने ही बनाये हैं. जब ज्यादा पानी आता है तो वह फ्लड प्लेन्स सारा पानी खींच लेता है. लोग उन्हीं फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन करने लगे जिस वजह से वहां उन्हें यह दिक्कत आने लगी. दीवार बनाकर कुछ समय के लिए तो इसे रोका जा सकता है, लेकिन यह कोई परमानेंट उपाय नहीं है. जब भी हम नेचर के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं तो हर लड़ाई में नेचर की ही जीत होती है. विशेषज्ञ खन्ना ने आगे बताया कि इन फ्लड प्लेन्स का भी अपना काम होता है अगर हम पानी का रास्ता ही बंद कर दें कि पानी फ्लड प्लेन्स तक आए ही नहीं और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है. अगर हम ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे नेचर के साथ तो हमारा ही नुकसान होगा और हमारे देश में कंस्ट्रक्शन का हाल भी कभी छुपा है. कई बार बिना उद्घाटन हुए ही नए ब्रिज टूट जाते हैं. हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. विशेषज्ञों का सुझाव है कि बाढ़ से निपटने के लिए प्राकृतिक तरीकों को अपनाना ज्यादा कारगर होगा. नदी के आसपास के प्राकृतिक बफर जोन को बढ़ाना और उसके प्रवाह को समझकर योजना बनाना ही लंबे समय में सुरक्षित और टिकाऊ समाधान साबित हो सकता है.

महिला आरक्षण- पहली बार संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं करा पाई मोदी सरकार; चाहिए थे 352 वोट, मिले 298

नई दिल्ली ।

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक पर लंबी और गहन चर्चा के बाद शुक्रवार (17 अप्रैल) मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। कुल 528 सांसदों ने वोट डाला, जिसमें 298 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 230 ने विपक्ष में मतदान किया। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोट प्राप्त नहीं हो सके। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि यह विधेयक आवश्यक समर्थन नहीं जुटा सका, इसलिए आगे की विधायी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके बाद संबंधित दो अन्य विधेयकों पर भी सरकार ने मतदान कराने का निर्णय नहीं लिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 12 वर्षों में यह पहली बार है जब मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

लंबी बहस के बाद फैसला

इस विधेयक पर सदन में करीब 21 घंटे तक विस्तृत चर्चा चली, जिसमें कुल 130 सांसदों ने भाग लिया। इनमें 56 महिला सांसद भी शामिल रहीं, जिन्होंने अपने-अपने पक्ष रखे। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और स्पष्ट किया कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में एससी-एसटी समुदाय की सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही, धर्म के आधार पर आरक्षण की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए शाह ने दक्षिणी और छोटे राज्यों को परिसीमन के बाद भी उनके उचित प्रतिनिधित्व का पूर्ण आश्वासन दिया है। वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री के इस कड़े रुख ने इस विधेयक के ऐतिहासिक महत्व और राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा; मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार नाकाम

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव की कोशिश थी। उनके मुताबिक, यह संविधान की मूल भावना पर हमला था, जिसे विपक्ष ने मिलकर रोक दिया।

बिल में क्या था प्रस्ताव?

संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव था। साथ ही 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की योजना शामिल थी। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था, ताकि आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार मिलें- प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को लोकसभा के सभी सदस्यों से महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में मतदान करने और ऐसा कुछ भी नहीं करने की अपील की जिससे देश की नारी शक्ति की भावनाएं आहत हों। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर मतदान से कुछ समय पहले मोदी ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है

और अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें। संसद के निचले सदन के सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और प्रस्तावित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 816 करने के लिए परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर भी मतदान करेगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, अब से कुछ समय बाद लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं अपील करता हूं कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मोदी ने अपील की, मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा, मैं सभी सांसदों से कहूंगा आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें।

सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली ।कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने खेड़ा की ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में पेश किए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को लेकर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए असम की संबंधित अदालत या गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कोर्ट ने उन्हें आज दोपहर के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने पवन खेड़ा द्वारा हाईकोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट पेश किए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए इस व्यवहार को अनुचित बताया। जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला पवन खेड़ा की उन टिप्पणियों और कानूनी शिकायतों से जुड़ा है जिनके चलते उन्हें असम पुलिस द्वारा पूर्व में हिरासत में लिया गया था। तब से वह कानूनी राहत के लिए ऊपरी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं।

श्योपुर हादसे पर सीएम मोहन ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान

श्योपुर । मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया है। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है जबकि 2 दर्जन लोग घायल हुए है। सीएम मोहन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा की है। साथ ही गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। वहीं पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत ने भी 10-10 हजार रुपए आर्थिक मदद की। सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 'श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के सिंगरपाल गांव में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से महिलाओं के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दुर्घटना में जो घायल हुए हैं, उनको उपचार प्रदान किया जा रहा है।' बता दें कि अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली

पलट गई, जिसके नीचे दबने की वजह से चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे है। इस दर्दनाक घटना के बाद से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ट्रॉली में सवार सभी लोग वीरपुर से विजयपुर के बढ़ौदा भात देने जा रहे थे। इसी दौरान वीरपुर के धूमस से विजयपुर के झारबड़ौदा गांव जाते समय बोरपुरा मोड पर ये दिल को दहलाने वाला हादसा हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद 12 लोगों को ग्वालियर रैफर कर दिया है। हादसे के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गई। लोग चीख-पुकार करने लगे और मदद के लिए लोगों को पुकारने लगे। इसी दौरान नीचे दबने की वजह से चार महिलाओं की मौत हो गई।

टायर फटने के बाद बस से टकराई कार, जिंदा जल गए पांच मासूम समेत 9 लोग

बंगलुरू । कर्नाटक के यादगिर जिले में शुक्रवार को मौत का एक ऐसा तांडव देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है। दरअसल, सुरपुर तालुक के शांतपुर क्रॉस के पास एक कार और निजी बस की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 10 लोगों में से नौ लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में पांच मासूम बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कॉम्पैक्ट यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) का टायर अचानक फट गया। टायर फटते ही ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर की दूसरी तरफ से आ रही निजी बस से जा टकराई। भिड़ंत होते ही कार आग का गोला बन गई। हादसे के वक्त कार में कुल 10 लोग सवार थे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक पृथ्वीक शंकर ने 9 मौतों की पुष्टि की है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और कार, दोनों ही पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अग्निशमन दल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी 20 यात्री सुरक्षित समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

गर्मी के बीच राजस्थान में बारिश, हरियाणा में ओले गिरे

नई दिल्ली । देश के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। गुरुवार को यूपी के बांदा में पारा 44.4°C, एमपी के नर्मदापुरम में 43°C, राजस्थान के बाड़मेर में 42.9°C रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में पारा 40°C से 45°C के बीच है। इधर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने से मंडी में रखा अनाज भीग गया। मौसम विभाग के मुताबिक, आज जयपुर समेत 5 से ज्यादा जिलों में बरसात हो सकती है। हरियाणा में भी शुक्रवार दोपहर को बारिश और ओले गिरे। छत्तीसगढ़ में हीटवेव के कारण 11 दिन पहले स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर-डिंडोरी में भी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में अगले 3 दिन लू का अलर्ट है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी लू चलेगी।

जन समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं अधिकारी, सीएम ने दिए निर्देश; जनता दर्शन में 200 लोगों की सुनी समस्या

गोरखपुर ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगातार दूसरे दिन, शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, घबराइए मत। सरकार, आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी। शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी बातें सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र लेकर उसका अवलोकन कर समस्या/शिकायत का संज्ञान लिया। फिर, अलग-अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित और हस्तगत किया। साथ ही निर्देश दिया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह शुक्रवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध कराएगी। कुछ महिलाओं ने आवास की समस्या मुख्यमंत्री को बताई। इस पर सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध कराने को संकल्पित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी पात्र लोग पक्के आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए।

ईरान ने खोला होर्मुज- भारत के लिए आई एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी

नेशनल डेस्क । होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से भारत समेत कई देशों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस गुजरता है। बता दें कि 28 फरवरी को ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ी, जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा था, इसने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी थी। इस आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह थी 'होर्मुज जलडमरूमध्य' का बंद होना। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने होर्मुज को व्यापार के लिए पूरी तरह से खोलने का ऐलान कर दिया है।

1. क्रूड ऑयल के गिरे दाम

देश में कच्चे तेल का 85प्रतिशत हिस्सा विदेशों से खरीदता है, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आने वाले तेल होर्मुज के रास्ते से भारत पहुंचता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने जैसे ही समुद्री रास्ते को खोलने का आदेश दिया, इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि शुक्रवार रात क्रूड ऑयल 12 प्रतिशत टूटकर 83 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, ब्रेंट क्रूड भी 11 फीसदी फिसलकर 87 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल काफी कम होगा। इससे सरकारी खजाने पर दबाव घटेगा और देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट सुधरेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक है।

2. शेयर बाजार होगा मजबूत

होर्मुज का रास्ता खुलना शेयर बाजार के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बंद होने के बाद यह अहम खबर आई, लेकिन 'गिफ्ट निफ्टी' में इसका असर तुरंत दिखा। गिफ्ट निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा (करीब 2 फीसदी) की छलांग लगा चुका है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सोमवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे, तो निवेशकों को शानदार शुरुआत देखने को मिलेगी। खासतौर पर कच्चे तेल के दाम गिरने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ-साथ पेंट, टायर और एविएशन सेक्टर के शेयरों में तगड़ी खरीदारी की उम्मीद है।

3. सोने-चांदी में भयंकर तेजी

मिडिल-ईस्ट में तनाव कम होने पर आमतौर पर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग रहे। बढ़ते तनाव के देखते हुए लोगों ने सोना-चांदी जैसी कीमती चीजें खरीदने बंद कर दी, क्योंकि कीमतों में भी लगातार उछाल आ रहा था। महज़ पर चांदी 5 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 2.61 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. वहीं, सोने में भी 1.50 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है, जिससे 10 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 1.55 लाख रुपये हो गया है।

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली । दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच राहुल गांधी के खिलाफ जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से शुक्रवार को ये आदेश दिया गया है. साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह स्वयं जांच करे या मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपकर जांच करवाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए साफ निर्देश दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जांच आगे बढ़ाई जाए. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के सामने अपने-अपने तर्क रखे. लंबी बहस के बाद कोर्ट ने यह

उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- सीबीआई जांच करे

साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह स्वयं जांच करे या मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपकर जांच करवाए.

स्पष्ट किया कि जांच जरूरी है. अदालत ने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता रखने के आरोपों की जांच आवश्यक है. दरअसल, यह पूरा मामला कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर की याचिका से शुरू हुआ था. शिशिर ने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है. इसी आधार पर उन्होंने रायबरेली में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. याचिका में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के साथ-साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग शामिल थी. आरोप यह भी था कि बतौर सांसद दो पासपोर्ट रखना कानून का उल्लंघन हो सकता है. हालांकि, पहले रायबरेली एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन हाईकोर्ट ने अब उस फैसले को निरस्त करते हुए मामले को नई दिशा दे दी है.